



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]

No. 361]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2005/भाद्र 7, 1927

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2005/BHADRA 7, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 544(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मुरगांव पत्तन कर्मचारी (चिकित्सा सेवा) (संशोधन) विनियम, 2005 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा - 124 के साथ पठित धारा - 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन का न्यासी मण्डल, मुरगांव पत्तन कर्मचारी (चिकित्सा सेवा), विनियम, 1969 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (चिकित्सा सेवा), (संशोधन) विनियम, 2005 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम, केन्द्र सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 3 में

(i) खण्ड (ग) के मौजूदा उप-खण्ड (vii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए - "पत्तन द्वारा नियोजित दिहाड़ी तथा नैमित्तिक श्रमिक, जब ड्यूटी पर घायल हो जाते हैं, तब वे न्यास के अस्पताल / डिस्पेन्सरी में उपलब्ध सुविधाओं तथा दवाइयों तक ही चिकित्सा सेवा / उपचार के हकदार होंगे। मंडल द्वारा नियोजित श्रमिकों के अलावा, पत्तन परिसरों के भीतर कार्य करने हेतु, पत्तन न्यास द्वारा नियुक्त संविदाकारों द्वारा नियोजित श्रमिक भी इन सुविधाओं के हकदार होंगे बशर्ते की संविदाकारों से तत्संबंधी खर्च की वसूली की जाएगी।"

[फा. सं. एच-11011/8/2003-पीई-1]
ए. के. भट्टा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

- i) केन्द्र सरकार की मंजूरी सं. पीडब्ल्यू/पीईजी - 39 / 79 दि. 6/6/1980
- ii) केन्द्र सरकार की मंजूरी सं. पीडब्ल्यू/पीईजी - 18 / 85 दि. 28/1/1986
- iii) सा. का. नि. सं. 70(ई) दि. 11/10/2002
- iv) सा. का. नि. सं. 708(ई) दि. 28 अक्टूबर, 2004

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Shipping)
(PORTS WING)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2005

G.S.R. 544(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees' (Medical Attendance) Amendment Regulations, 2005 made by the Board of Trustees of Mormugao Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following regulations further to amend Mormugao Port Employees' (Medical Attendance), Regulations, 1969 namely:

1. (i) These regulations may be called the Mormugao Port Employees' (Medical Attendance) (Amendment) Regulations, 2005.

(ii) They shall come into force with effect from the date from which the approval of the Central Govt. is published in the Gazette of India.

2: In Regulation 3:

(i) Substitute existing Sub-Clause (vii) of Clause (C) with the following:

" daily rated and casual labour employed by the Port when injured on duty, shall be entitled to medical attendance/treatment to the extent those facilities and medicines are available in Trust's Hospital/dispensary. Labour, other than employed by the Board, such as those employed by the contractors engaged by the Port for performing duty within the premises of the Port Trust are also entitled to such benefits, subject to recovery of cost from the contractors."

[F. No. H-11011/8/2003-PE-I]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Foot Note :-

- (i) Central Government's sanction No. PW/PEG-39/79, dated 6.6.1980
- (ii) Central government's sanction No. PW/PEG-18/85, dated 28.11.1986
- (iii) GSR No. 70(E), dated 11.10.2002.
- (iv) GSR No. 708 (E) dated 28th October, 2004.